International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 5.143, Volume 02, No. 04, October - December, 2020, pp.257-260

देश के आर्थिक विकास में मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ एवं दोषों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

कल्पना शर्मा*
डॉ. नीरज बासोतिया**

सार

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप, गुण व दोषों को समझना अति आवश्यक होता है ताकि उसकी कमियों व कठिनाइयों को दूर करके उसमें आवश्यक सुधार किए जा सकें जिसके आर्थिक विकास की गतिशीलता में वृद्धि की जा सके। उदाहरण के रूप में जब सन् 1929 में विश्व के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को आर्थिक महामंदी का झटका लगा तो अमेरिका सहित पश्चिम यूरोप के कई देशों को भारी बेरोजगारी, मांग और आर्थिक गतिविधियों में कमी तथा उद्योग धंधों पर तालाबंदी जैसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में समाजवाद और पूँजीवाद दोनों ही एकल रूप में समस्या से बाहर निकल पाने में नाकाम रहे। इसलिए यह कहना गलत भी नहीं होगा कि वह देश अपनी अर्थव्यवस्था की प्रणालियों के गुण व दोषों को भायद ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाए।

मुख्य शब्दः *मिश्रित अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास।*

प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत ने उपनिवेशवाद के जिस दंश को झेला उसने भारत की अर्थव्यवस्था को तहस–नहस कर दिया था। सन् 1947 में आजादी मिलने के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को गरीबी और भूखमरी के जाल से बाहर निकाला जाए। दोनों ही प्रणालियों (पूँजीवादी और समाजवाद) के दोषपूर्ण होने के कारण यह आवश्यकता समझी गई कि एक ऐसी प्रणाली अपनाई जाए जिसमें पूँजीवाद की स्वतंत्रता तो हो लेकिन वह स्वतंत्रता सरकार की नीतियों द्वारा संचालित एवं नियंत्रित हो तथा सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को एक समाजवादी आधार दे सके। इसके लिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह–अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। इस प्रणाली में सरकार निजी क्षेत्र में अपना प्रत्यक्ष व सार्वजनिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप रखती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्शों बाद भी भारत विकास की उस सीमा तक नहीं पहुँच पाया है जिसके लिए उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया था। इसके लिए भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष ही जिम्मेदार हैं, जिन्हें दूर करके आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान की जा सकती है।

G शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझनू, राजस्थान।
** असिस्टेन्ट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझनू, राजस्थान।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ

- **आर्थिक विकास की गतिशीलताः** देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए सरकार ने आर्थिक नियोजन की नीति को अपनाया है। इस नीति के माध्यम से सरकार संसाधनों का विभाजन निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बीच इस प्रकार करती है जिससे सभी संसाधनों का उचित दोहन सम्भव हो सके। किसी भी देश में अर्थव्यवस्था के संसाधनों का उचित दोहन उस देश के आर्थिक विकास के लिए अति आव यक होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों इस प्रकार साथ मिलकर कार्य करते हैं जिससे देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। इसलिए इस आधुनिक समय में मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास की आव यक प्रणाली है।
- **आर्थिक भाक्ति के केन्द्रीकरण एवं एकाधिकारी भाक्ति पर रोकः** मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार को आर्थिक क्रिया के क्षेत्र में सकारात्मक भाग अदा करना पड़ता है इसलिए इस प्रणाली में सरकार निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण द्वारा अपनी विभिन्न नीतियों को इस प्रकार निर्देशित करती है जिससे समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व का बेहतर वितरण एवं नियंत्रण प्राप्त हो सके और इससे कुछ व्यक्तियों (पूँजीपतियों) के हाथों में सम्पत्ति का संकेन्द्रण और श्रम का शोषण होने से रोका जा सके।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार आवश्यकता पड़ने पर समाज कल्याण के लिए राष्ट्रीयकरण द्वारा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण एवं एकाधिकारी शक्ति पर रोक भी लगा सकती है।

- **कल्याणकारी राज्य की स्थापनाः** मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाना होता है ताकि निर्धनता को दूर किया जा सके। इसमें सरकार अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ आय की असमानता और उसके कारण उत्पन्न विसमताओं का निवारण करने का प्रयास करती है। सरकार अर्थव्यवस्था का नियंत्रण और कार्य संचालन संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखकर ही कार्य करती है ताकि समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित हो सके।
- **औद्योगिक भान्ति की स्थापनाः** मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार अपनी विभिन्न प्रकार की औद्योगिक नीतियों के माध्यम से उद्यमियों एवं श्रमिकों के संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करती है ताकि इन दोनों के टकराव के कारण आर्थिक विकास पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े और अर्थव्यवस्था अपने सुचारू रूप से कार्य करके गतिशील बनी रहे। श्रमिक वर्ग को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए सरकार अपनी सभी औद्योगिक नीतियों में उनके हितों का ध्यान रखती है। इसी कारण यहाँ पूँजीवाद की तरह हड़ताल, तालेबन्दी आदि जैसी समस्याऐं उत्पन्न नहीं होती हैं।

सरकार वृद्धावस्था पेंशन, जीवन बीमा, बेरोजगारी भत्ता आदि के माध्यम से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के साथ–साथ उनके हितों की गारंटी भी देती है। जिसके कारण औद्योगिक भान्ति स्थापित रहती है।

- **मानव संसाधनों का समुचित दोहनः** मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार अपने अथक प्रयासों से बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर एक कुशल कार्यबल का निर्माण करती है। सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन यह ध्यान में रखकर ही करती है कि कुशल एवं शिक्षित कारीगरों द्वारा ही एक सुदृढ़ एवं सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव होता है क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के मानव संसाधनों के उचित प्रयोग से ही सुनिश्चित किया जाता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष

- अस्थिरताः भारत में सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सरकार का कार्यकाल समाप्त होने पर नई सरकार अस्तित्व में आती है और सरकार के बदलने के साथ ही उनकी नीतियों में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण उन नीतियों के स्थिरता की कमी पाई जाती है। इसी अस्थिरता के कारण इन

नीतियों का पूर्ण प्रतिफल समाज को प्राप्त ही नहीं हो पाता क्योंकि यह नीतियाँ ठीक प्रकार से निश्चित समय पर कार्यान्वित नहीं हो पाती है। इस कारण अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है और आर्थिक विकास की गतिशीलता भी उस गति से नहीं बढ़ पाती जिस गति से बढ़ना चाहिए।

- **प्रायोगिकता में कमजोर आर्थिक प्रणालीः** मिश्रित अर्थव्यवस्था की सफलता पर आलोचकों द्वारा जो भिन्न–भिन्न प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते रहें हैं, उनका आधार यह है कि इस प्रणाली में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सह–अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है जबकि दोनों ही क्षेत्रों की कार्य–प्रणाली एवं नीतियों में विरोधाभास होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों क्षेत्र किस प्रकार उचित सामान्जस्य के साथ देश की आर्थिक वृद्धि एवं समाज कल्याण दोनों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों ही क्षेत्रों में उचित सामन्जस्य न बैठ पाने के कारण विभिन्न निर्णयों में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि कीमत संयन्त्र न तो पूँजीवाद की तरह पूर्ण रूप से लागू हो पाता है और न ही समाजवाद की तरह नियंत्रित परिणाम यह होता है कि अर्थव्यवस्था का संचालन सकुशल रूप से नहीं हो पाता क्योंकि दोनों क्षेत्रों के बीच कीमत संयन्त्र एवं नियोजन के बीच सामन्जस्य न बैठ पाने के कारण दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं।

- **पूर्णरूपेण सरकारी नियंत्रण का भयः** मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सदैव सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण का भय बना रहता है, जिसके कारण उद्योगपतियों में निवेश के प्रति उदासीनता का भाव रहता है। इसके अतिरिक्त विदेशी उद्यमी भी राश्ट्रीयकरण के भय के कारण देश में अपनी पूँजी विनियोग करने से बचते हैं, जिसके फलस्वरूप पर्याप्त निवेश न होने पर देश के आर्थिक विकास में अत्यधिक वृद्धि नहीं हो पाती है।
- **सरकारी अफसरों एवं कर्मचारियों की निरंकुश कार्यप्रणालीः** मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन भाासन एवं प्रशासन दोनों के माध्यम से किया जाता है। जिसमें प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही के कारण नागरिकों की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अनेकों ऐसे कार्य जिनका समय से पूरा होना अति आव यक होता है, वह समय से पूर्ण नहीं हो पाते हैं। इनकी इस उदासीन कार्य प्रणाली से भ्रश्टाचार जैसी बीमारी को बढ़ावा मिलता है तथा इस भ्रश्टाचार के कारण ही सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का उचित एवं समयबद्ध कार्यान्वयन नहीं हो पाता है।
- **कीमत वृद्धि दरः** मिश्रित अर्थव्यवस्था में अस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं जैसे चीनी, जूते, वनस्पति तेल आदि की वृद्धि दर की अपेक्षा स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं जैसे सीमेंट, ईंट, पत्थर आदि के उत्पादन की वृद्धि दर ज्यादा रही हैं। परिणामस्वरूप अस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वालों को अपनी लागत की उचित कीमत नहीं मिल पाती और इसी कारण उनका आर्थिक विकास में योगदान पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं हो पाता है।

निष्कर्ष

मिश्रित अर्थव्यवस्था के उपर्युक्त अध्ययन के विश्लेशण से यह बात स्पष्ट होती है कि भारत जैसे विकासशील एवं अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश का विकास न तो पूरी तरह पूँजीवाद को अपनाकर किया जा सकता है और न ही समाजवाद को अपनाकर। इसलिए देश के सन्तुलित एवं तीव्र विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था एक आवश्यक प्रणाली है। इस प्रणाली में वह क्षमता विद्यमान है जो देश के सभी सीमित संसाधनों का उचित एवं कुशल उपयोग संभव कर सके, जिसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक विकास की उस तीव्र गति का प्राप्त कर सकती है जो देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला सके।

इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बावजूद भी इसकी कमियों को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक–आर्थिक न्याय का उद्देश्य होने के बावजूद भी यह प्रणाली मूल्य–वृद्धि रोकने तथा समाज के गरीब वर्गों के हित में संसाधनों के पुनर्वितरण में भी असफल रही है। लेकिन वि लेशण से यह

भी स्पष्ट होता है कि इसमें व्याप्त दोश मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण नहीं हैं बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस व्यवस्था की नीतियों को सही तरह से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन एवं उसके द्वारा बनी नीतियों का ध्यानपूर्वक क्रियान्वयन किया जाए तो इसके दोशों का निवारण करना उतना कठिन भी नहीं है जितना हमें लगता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव निम्न प्रकार हैः

- प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही को समाप्त किया जाए।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को कम करने के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाए।
- सरकार द्वारा बनाई गई जनकल्याणकारी नीतियों का उचित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए।
- समाज के गरीब वर्गों के हित में संसाधनों का उचित रूप में पुनर्वितरण होना चाहिए।
- भारत के कृषि क्षेत्रों के विकास को सुदृढ़ करके किसानों को सबल, सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने की आवश्कता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- भारतीय अर्थव्यवस्था–रूद्रदत्त एवं सुन्दरम
- विकास एवं नियोजन–एम.एल. झिगंन
- योजना पत्रिका
- दैनिक समाचार पत्र
- कुरुक्षेत्र पत्रिका (मासिक पत्रिका)
- भारतीय आर्थिक समस्याएं– डॉ0 जे0सी0 पन्त, डॉ0 जे0पी0 मिश्रा
- आर्थिक विकास एवं नियोजन–एस0पी0 सिंह
- आर्थिक विकास के सिद्धान्त–रेणु त्रिपाठी
- भारतीय अर्थव्यवस्था–रमेश सिंह
- भारतीय अर्थव्यवस्था–उमा कपिला
- भारतीय अर्थव्यवस्था–मिश्रा और पुरी
- प्रतियोगिता दर्पण भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषांक
- इकोनॉमिक एवं पोलिटिकल वीकली
- सरकार द्वारा प्रकाशित विभिन्न आर्थिक योजनाओं संबंधी भोध पत्रों का अध्ययन
- आर्थिक समीक्षा के विभिन्न संस्करण
- इण्डिया टुडे पत्रिका
- विकास एवं नियोजन–वी0सी0 सिन्हा
- भारतीय अर्थव्यवस्था–गौरव दत्त, अश्वनी महाजन.

❖◆❖